SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Even for Section 144 violation. ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: No, no. Preventive detention is excluded. That is not true. Preventive detention is excluded. ...*(Interruptions)*... It is preventive in nature. But, anyway, I am deeply obliged to the distinguished Members of this House to have unanimously supported this Amendment. I commend this to the Members of this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted

SHORT DURATION DISCUSSION

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Short Duration Discussion on abnormal rise in prices of onion and other essential commodities. Shri Naresh Agrawal to raise the discussion.

DR. V. MAITREYAN: Sir, this abnormal price rise should not be abnormally stretched beyond time. ...*(Interruptions)*...

Abnormal rise in the prices of Onion and other essential commodities

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज इस सदन में चर्चा होने जा रही है और मैं समझता हूं कि अगर इसका जवाब माननीय

वित्त मंत्री दें तो ज्यादा उचित होगा। जो सरकार आंकड़ों पर विश्वास रखती है, सत्यता पर विश्वास नहीं रखती है, वह जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं होती। आज यही हाल इस मौजूदा सरकार का है। वित्त मंत्री जी भी आंकड़ों पर विश्वास रखते हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, ये भी आंकड़ों में जवाब देंगे। आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों की हेराफेरी से हो सकता है कि वे अपने मन में विश्वास पैदा कर लें, संतुष्टि दे दें, लेकिन जब तक आम जनता संतुष्ट नहीं होती तब तक आंकड़ों की बाजीगरी कोई काम नहीं करती। आज इसी आंकड़ों की बाजीगरी पर सरकार जो काम कर रही है, वही कारण है कि आज जनता में यह सबसे अलोकप्रिय सरकार है और अगर चुनाव कराए जाएं तो आपको पता लगेगा कि आपकी लोकप्रियता या अलोकप्रियता कहां तक है। कई बार सदन में चर्चा हुई और मैं सोचता था कि सरकार चर्चा के बाद गंभीर होगी, लेकिन मुझे सरकार की गंभीरता कहीं दिखायी नहीं दी। अभी सरकार ने कह दिया कि हमारा थोक सूचकांक 8.33 है और यह भी 13 से घटकर नीचे आ गया है। अब इन्हें फुटकर सूचकांक दिखायी नहीं दे रहा है। आप लोग जीडीपी की बात कर रहे हैं, वह भी ठीक नहीं है। आपकी फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, मनी का डिवैल्युएशन हो रहा है। ये सब चीजें महंगाई पर मार कर रही हैं और इस सब का देश की जनता पर प्रभाव पड़ रहा है। आज अखबार में था कि इस सत्र के समाप्त होने के बाद डीजल की प्राइस 5 रुपए और बढ़ा दी जाएगी। यह 5 रुपए डीजल के प्राइस बढ़ने की बात नहीं है, उसका ऑफ्टर इफेक्ट हर चीज पर कितना पड़ेगा, अगर इस बारे में सरकार सोच लेती तो सरकार को सत्यता पता लग जाती।

महोदय, योजना आयोग ने पहले गरीबी की परिभाषा 18 और 23 रुपए दी थी, अब उसने 26 और 33 कर दी अर्थात गांव में रहने वाले जिस व्यक्ति की आय 26 रुपए है, वह गरीब नहीं रहा और शहर में जिस की आय 33 रुपए है, वह गरीब नहीं रहा। महोदय, आज इस कीमत में तो डिस्टिलरी वाटर नहीं मिल रहा है। देश में पहले एक रुपए में चाय का कप मिलता था, वह भी रेलवे स्टेशन पर 10 रुपए में मिलने लगा है। मैं राज बब्बर जी का बयान पढ़ रहा था कि 5 रुपए में मुम्बई में आप भरपेट बढ़िया खाना खा सकते हैं। फिर इसी सदन के सदस्य रशीद मसूद जी का भी बयान आया और उन्होंने भी इसी तरह का बयान दे दिया। मंत्री जी, आप फूड बिल पर मंडे को सदन में चर्चा करेंगे। आप फूड बिल इसलिए लाए क्योंकि इस देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। वह उस रेट पर गेहूं, चावल नहीं खरीद सकती और जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए आपकी नेता सोनिया जी ने इसे अपनी प्रेस्टिज इश्यू बनाया। इस में आप ने खुद कहा है कि देश में अभी भी 67 प्रतिशत आबादी गरीब है। आप प्रचार कर रहे हैं कि हम फूड बिल से इस देश के 67 प्रतिशत भूखे-नंगे लोगों को भूखे पेट नहीं सोने देंगे। अगर पूरे विश्व में हमारे देश की यह तस्वीर बनी कि 67 साल की आजादी के बाद, आज भी हिंदुस्तान में भूखे-नंगे हैं, तो फिर विश्व में हमारी क्या इमेज बन रही है? क्या हम विश्व में वोटों के लिए अपनी यही इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं? अगर हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो आज अमेरिका हम से दोस्ती इसलिए कर रहा है क्योंकि हिंदुस्तान विश्व की सब से बड़ी मार्केट है। आज

[श्री नरेश अग्रवाल]

चाइना, दुश्मन होते हुए भी, हिंदुस्तान से इसलिए वार्ता करता है क्योंकि उसे इस से बड़ी कोई मार्केट नहीं मिल सकती। आज विश्व की सब से बड़ी कंज्यूमर्स मार्केट हिंदुस्तान है। इसलिए हमें इस बारे में भी सोचना पड़ेगा।

महोदय, जब डबल्यूटीओ एग्रीमेंट लागू हुआ, तो इस बात की आशंका व्यक्त की गयी थी कि हिंदुस्तान के अंदर इतना विदेशी माल आ जाए कि हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इम्बैलेंस हो जाए। आज वही हालत है कि हमारा इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया है, लेकिन एक्सपोर्ट घटता चला गया है जिसका नतीजा आज हम हर चीज में भुगत रहे हैं। हम रुपए का अवमूल्यन नहीं रोक पा रहे हैं। आज टी0वी0 पर दिखाया जा रहा था कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य 66 तक पहुंच गया। इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए कि यह अवमूल्यन कहां रुकेगा। उन्होंने कहा कि रुपया अपने आप स्थान ढूंढ लेगा। इस देश में सभी अपने आप स्थान ढूंढ लेते हैं, उसके लिए सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही रुपया भी ढूंढ लेगा, लेकिन आप क्यों असफल हो रहे हैं? आप की कमी कहां है? आप अपनी कमी क्यों छिपाना चाहते हैं? गांधी जी ने कहा था कि नेता वह बड़ा होता है, जो अपनी आलोचना सुने, जो अपनी कमियों को स्वीकार करे और सरकार वह बड़ी होती है, जो आलोचना को सुने व उसे स्वीकार करे। हम आप की आलोचना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम आपके विरोधी हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि आप देश में कुछ ऐसा निर्णय लें कि यह देश समृद्ध बन सके, देश आगे बढ़ सके। जो हिंदुस्तान "सोने की चिड़िया" कहलाता था, वह हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बने और हमारे देश का पूरे विश्व में आदर हो।

आज हमारी स्थिति क्या है? प्याज़ का मूल्य क्या हो गया है? 80 रुपए किलो प्याज़। पता नहीं आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैसा है कि आप यह देख ही नहीं पा रहे हैं कि किस मौसम में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है। अब आपने कह दिया कि नैफेड प्याज़ ले आएगा, तो जब आपको मालूम था, तो क्यों नहीं आपने पहले ही नैफेड को दे दिया? इसका जवाब आया, शरद पवार जी का बयान मैं पढ़ रहा था कि नासिक में कम बारिश के कारण प्याज़ का उत्पादन कम हुआ, इसलिए देश में प्याज़ की कमी हुई। बारिश तो दो महीने पहले कम हुई होगी, तो दो महीने पहले ही आपने नैफेड से क्यों नहीं कहा कि विदेश से प्याज़ ले आओ? दो महीने के बाद जब प्याज़ की कीमत बढ़ गई, महोदय, आज केवल प्याज़ का ही सवाल नहीं है, दाल है, रोटी है, दूध को ले लीजिए, दूध के प्राइस, बिसलेरी वॉटर और तमाम तरह के वॉटर के जो प्राइसेज हैं, आप कैसे उन प्राइसेज के बल पर कह सकते हैं कि हमारे यहां महंगाई नहीं है? न हो, तो आप आंकड़े दे दीजिए। आंकड़े भी आप सत्यता पर दीजिएगा। मैं आंकड़ों पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो चाहूंगा कि सत्यता पर विश्वास हो, चीज़ें सत्यता पर आएं, जिससे कम से कम जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज महंगाई पर इस बड़े सदन में चर्चा हो रही है, तो कम से कम मंत्री जी, एक जिम्मेदार उत्तर आपकी तरफ से आना चाहिए और

ऐसा लगना चाहिए कि वाकयी में केंद्र की सरकार इन चीज़ों पर गंभीरता से विचार कर रही है और सरकार कोई ऐसा निर्णय लेगी, जिससे देश के लोगों को लगेगा कि हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिस हिंदुस्तान में सोने की चिड़िया रहती थी। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिसने अपने लिए सब कुछ किया।

महोदय, डीज़ल और पेट्रोल के दाम इस साल कम से कम छः या आठ बार बढ़ चुके हैं और अभी कितनी बार और बढ़ेंगे, पता नहीं। आप बता दीजिएगा। शायद आप यह न बता पाएं क्योंकि यह आपका विषय नहीं है, लेकिन आपने गैस सिलेंडर की सीमा बांध दी। जब चुनाव आएगा, तो महिलाएं बताएंगी कि सीमा कितनी है, क्योंकि हम पुरुषों का तो गैस सिलेंडर से ज्यादा वास्ता नहीं रहता है, लेकिन उलाहने तो हम लोगों को सुनने ही पड़ते हैं। गैस सिलेंडर पर आपने सीमाएं बांधी हैं, तो आप सीमा क्यों बांध रहे हैं? या तो फिर आप सब्सिडी दीजिए ही नहीं, अगर दे रहे हैं तो फिर सबको सब्सिडी दीजिए। आप हर चीज़ पर सीमा कैसे बांध देंगे? माननीय वित्त मंत्री जी ने सोने पर भी टैक्स बढ़ा दिया! अब तो महिलाएं सोना पहनती नहीं हैं। आप मंगा लीजिए, अब तो सारा आर्टिफिशियल सोना मिल रहा है, आर्टिफिशियल मोती मिल रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं के लिए जो आभूषण थे, उनको भी आप रोक रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और जो फॉरेन एक्सचेंज है, वह घट रहा है। उस घटे हुए फॉरेन एक्सचेंज को रोकने के लिए आपने यह कर दिया। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां है? आज आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ दो परसेंट से नीचे चली गई है। हमारे पास कोयला है, लेकिन हम कोयले की एक भी खान से कोयला नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे पास गैस है, लेकिन एक पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए उस गैस को निकलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस पूंजीपति को जब तक इंटरनेशनल मार्केट का पैसा नहीं मिलेगा... आज हम चार प्वाइंट और कुछ डॉलर में गैस का दाम दे रहे हैं। प्रस्ताव आपने आठ प्वाइंट कुछ किया है और आप कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट 13 डॉलर की है, तो जब तक 13 डॉलर की गैस हम नहीं कर देंगे, तब तक देश में गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि उनके बिना आपकी सरकार नहीं चलेगी। वे जब मंत्रालय बदलवा देंगे, अगर गैस का पेट्रोलियम मंत्री एक पूंजीपति के कहने पर बदला जाएगा, हो सकता है कि कल आप भी बदल दिए जाएं, गारंटी नहीं है, लेकिन आप मंत्री हैं, तो हम आपका जवाब सुनेंगे, लेकिन अगर देश का पेट्रोलियम मंत्री एक पूंजीपति के कहने पर बदल दिया जाएगा, तो फिर काहे की सरकार? क्या बात करें? कहां इस देश को फायदा होने जा रहा है? इस देश की ग्रोथ कैसे होगी? आप देश की ग्रोथ की बात करते हैं और कहते हैं कि हम इस देश को आगे ले चलेंगे, लेकिन देश की निरंतर जो स्थिति होती चली गई, इस सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में आपने इस देश को यूरोप बनाने का संकल्प लिया है, इस देश को अमेरिका बनाने का संकल्प लिया है, इस भारत को गरीब देश रखने का संकल्प नहीं है आपका और आपका कहना है कि हम इस देश को जब तक यूरोप नहीं बनाएंगे, अमेरिका नहीं बनाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तो हो सकता है कि आप इस समय चैन से बैठे हों कि आप देश को यूरोप और अमेरिका बना रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? श्रीमन्, बैंक ऋण का

[श्री नरेश अग्रवाल]

ब्याज बढ़ा दिया गया। जिन बच्चों ने पढ़ने के लिए बैंक से लोन लिया, जिन किसानों ने खेत के लिए बैंक से लोन लिया, आज उनकी ईएमआई कितनी बढ़ गई? आज रुपए का अवमूल्यन हो गया। ईएमआई इतनी बढ़ गई कि जो उसने 8 परसेंट पर लोन लिया, आज उसको 12-13 परसेंट पर रिटर्न देना पड़ रहा है, तो इस 4-5 परसेंट में तो बहुत लोगों की स्थिति खराब हो गई और देश में शिक्षा-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज इस वजह से खाली हो गए।

आज पिता अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च नहीं दे पा रहे हैं। आज सवेरे मैंने इसी बात को उठाया था। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, सुबह मैंने यही बात कही थी कि हम फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में जब बैंकों की समीक्षा कर रहे थे तो हमारे सामने जो एनपीए अकाउंट आए, उनके संबंध में अधिकांश बैंकों ने कहा कि 60 परसेंट एनपीए अकाउंट उन लोगों के हैं, जिनके ऊपर दस लाख रुपए से कम का कर्जा है या दस लाख रुपए तक का कर्जा है, यानी वे लोग किसान और स्टूडेंट्स हुए। 30 परसेंट उन लोगों के एनपीए अकाउंट हैं, जिनके ऊपर दस लाख से दस करोड़ रुपए तक का कर्जा है और पांच परसेंट उनके अकाउंट हैं, जिन पर दस करोड़ से ऊपर का कर्जा है। बैंकों द्वारा एनपीए की यह स्थिति बतायी गयी। आपका एनपीए अकाउंट एक परसेंट से बढ़कर चार परसेंट हो गया है। विश्व के किसी भी देश में बैंक का एनपीए अकाउंट एक परसेंट से ऊपर नहीं होता है। आज आप एनपीए में चार परसेंट तक चले गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपके बैंक फ्लॉप हो जाएं, आप अमेरिका की तरह न हो जाएं कि हिन्दुस्तान के बैंकों पर भी लोगों का विश्वास उठ जाए। बहुत से कोऑपरेटिव बैंक फेल हो गए, बहुत से प्राइवेट बैंक फेल हो गए, लेकिन अगर आपके एनपीए अकाउंट की वजह से नैश्नलाइज्ड बैंक फेल होने की स्थिति में आ गए तब आप क्या करेंगे? इस संबंध में आप क्या विचार कर रहे हैं? अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ये सब महंगाई से जुड़े हुए प्रश्न हैं। सर, मैं ऐसे बिन्दू उठा रहा हूं जो इस देश से जुड़े हैं, महंगाई से जुड़े हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर वित्त मंत्री जी आकर इसका जवाब दें तो शायद वे ज्यादा अच्छा जवाब देंगे क्योंकि आप तो प्याज, आलू और गृहस्थी का जवाब देंगे, वे देश का जवाब दे देते। यहां गृहस्थी और देश, दोनों का जवाब आना जरूरी है। सर, दो मंत्री एक साथ जवाब दे नहीं सकते हैं इसलिए हमने सोचा कि अगर बड़े मंत्री जी जवाब दे देंगे तो दोनों चीजों का एक साथ जवाब मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इस बात का जवाब आप अच्छे तरीके से दें। मुझे आशा है कि इसे गंभीरता से लेते हुए आप इस बात का जवाब देंगे।

श्रीमन्, आज यह स्थिति हो गयी है कि हिन्दुस्तान के जितने उद्योगपति हैं, वे सारा निवेश विदेश में कर रहे हैं -- पूरा साउथ, पूरी अफ्रीकन कंट्रीज़, सारा यूरोप -- आप इस

कंट्री का पिछले एक साल का इन्वेस्टमेंट उठाकर देख लीजिए कि इस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। मैं रोज़ पढ़ता हूं, पास्को चला गया, अम्बानी ने विदेश में माइन्स ले लीं, फलां उद्योगपति विदेश में कारखाना लगाने जा रहे हैं, बिरला ने भी यहां पर बंद कर दिया, कहने लगे कि हम विदेश में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहां पर कोई ग्रोथ ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज यहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, बिजली नहीं है, कोयला आप दे नहीं सकते, गैस आप दे नहीं सकते। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वह इतनी ज्यादा आ रही है कि हम चाइना की मार्किट से कम्पीट नहीं कर सकते। धीरे-धीरे हमारे छोटे-छोटे गणेश, लक्ष्मी और होली की पिचकारी भी चाइना बनाकर भेजने लगा है। गांव में कुम्हार दीया बनाने का काम करता था, उसका वह काम खत्म हो गया, लुहार जो काम करता था, वह जो कंछली वगैरह बनाता था, उसका काम भी खत्म हो गया। स्थिति यह होती जा रही है कि एक छोटी से छोटी व्यवस्था पर चीन अटैक करता जा रहा है। चीन हमारी अर्थव्यवस्था को भी तोड़ रहा है और सीमा को भी तोड़ रहा है, दोनों को तोड़ रहा है, लेकिन हम इस बारे में सचेत नहीं हैं, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम इस संबंध में निर्णय क्या लें? हम दोनों प्रकार के निर्णयों में असफल हो रहे हैं। अगर इस देश का इन्वेस्टमेंट चला गया तो अनइम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा? आप देखें कि आज अनइम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है? मैं मीडिया के बारे में भी पढ़ रहा था। आज जो इतना बड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है, वह भी धीरे-धीरे छंटनी करने में जुट गया है। आईबीएन-7 वगैरह में करीब ढाई तीन सौ लोगों को निकाल दिया गया। उसमें पत्रकार साथी भी थे।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सिर्फ एक का नाम मत लीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल: हमारे न्यूज-24 से भी तमाम लोग निकाले जा रहे हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपने अखबारों का नाम नहीं लिया, अखबारों का नाम भी लीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल: अब हरेक का रहने दीजिए। महोदय, धीरे-धीरे यह स्थिति हो गयी है कि हमारे मीडिया के साथी भी अनइम्प्लाइड हो रहे हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि विश्व में हम ऐसा देश हैं जहां आज भी साठ परसेंट यूथ हैं। विश्व के किसी भी देश में इतने यंग लोग नहीं हैं, जितने हिन्दुस्तान में हैं। चाइना ने एक बच्चे के बाद प्रतिबंध लगा दिया, आज चाइना के सामने यह समस्या पैदा हो गयी है कि वहां यंग जेनरेशन कहां से आए? आज अमेरिका में बहुत अधिक वृद्ध हैं आज जापान में इतने वृद्ध हो गए हैं कि उनको रखने के लिए उन्हें आस्ट्रेलिया में जमीन लेनी पड़ी। हमारे पास जो कुछ है अगर हम उसको भी खोने लगेंगे तो हम देश के लोगों को क्या देंगे? आखिर सरकार किसलिए है?

श्री उपसभापति: नरेश अग्रवाल जी, अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, मैं अभी समाप्त कर देता हूं, आपका आदेश तो मैं कभी काटता ही नहीं हूं। हमारा विश्वास सरकार पर नहीं है, लेकिन चेयर पर जरूर है। हम तो सोच

[श्री नरेश अग्रवाल]

रहे थे कि आप सुन रहे हैं इसलिए हम बोलते चले जा रहे थे। अगर आप पहले कह देते,तो हम कम बोल देते, इसमें क्या था? मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अब कतरनी न चला दीजिएगा, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय मंत्री जी हमारे देश का टूरिज्म भी बहुत अफेक्टिड हो रहा है। आप उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, अभी तक चावल मिल -- जो चावल उत्पादित करते थे, उसमें से 75 परसेंट लेवी पर देते थे, आपने इसको 75 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट कर दिया है। आपने कहा कि हम 75 परसेंट नहीं लेंगे, हम 25 परसेंट लेंगे जिसकी वजह से यह उद्योग भी बंद होने जा रहा है। आप पीडीएस में और फूड सिक्योरिटी बिल में चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, लेकिन जब आप चावल लेने में कटौती कर रहे हैं, तो आपको चावल कहां से मिलेगा? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चावल उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है, दोनों जगह पर आपने चावल मिलों के लिए आदेश जारी कर दिया कि हम सिर्फ लेवी में चावल 25 परसेंट लेंगे, जबकि हर साल आप 75 परसेंट चावल लेते थे। यह आदेश आपने क्यों जारी किया, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में आप सदन को बताएं। हो सकता है कि केरल में इतना चावल न पैदा होता हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का राइस मिल उद्योग बंद होने जा रहा है। इससे आप और लोगों को बेराजगार करते जा रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप रोजगार दीजिए, इस देश के लोगों को मौका दीजिए, देश के लोग चाहते हैं कि हम हिन्दुस्तान के लिए काम करें, हमें विदेश में न जाना पड़े, इस देश से महंगाई हटे, प्याज और सब्जी सस्ती हो। महिलाओं से दुश्मनी बड़ी खराब होती है। आप तो मैरिड होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं कभी अपनी भाभी से मिला नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब आप घर जाते होंगे, तो आपको भी उलाहने सहने पड़ते होंगे। इन उलाहनों से बचने के लिए मैं चाहूंगा कि आप ऐसे कदम उठाइए जिससे कि ये महंगाई रुके और देश में गृहस्थी चल सके और लोग कह सकें कि हम उस हिन्दुस्तान में रहते हैं जिस हिन्दुस्तान में कभी सोने की चिड़िया रहती थी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद नरेश जी। श्री बलबीर पुंज।

श्री बलबीर पुंज (ओडिशा): उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, यह ठीक है कि इस अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत देश में प्याज की भारी कमी और उसके बढ़ते हुए दामों पर इस देश की चिंता से हुई है। हमने इस विषय को माननीय सभापति जी के सामने रखा और बाद में ध्यान में आया कि देश में न केवल प्याज की कमी है, न केवल प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, बल्कि सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और इसलिए यह जो अल्पकालिक चर्चा थी, यह प्याज तक सीमित न रहकर जो महंगाई की समस्या है, उस पर केन्द्रित है।

(उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी) पीठासीन हुईं)

उपसभाध्यक्ष महोदया, हम जानते हैं कि प्याज का भारत के लगभग सभी भागों में और सभी तरह के भोजन में भारी उपयोग होता है। एक समय तो यह भी कहा जाता था कि जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वह अगर और कुछ नहीं खा सकता तो कम से कम प्याज के साथ रोटी खाकर अपना पेट भर सकता है। परन्तु अब प्याज विलासिता की वस्तु बन गई है। It has become a luxury. प्याज खाना अब अपने आप में रईसी की निशानी हो गई है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, प्याज के ऊपर आज बहुत सारे चुटकले बन गए हैं। जब जनमानस किसी समस्या को लेकर उद्वेलित होता है, तो वह कठिन समय को हंसी के साथ काटना चाहता है इसीलिए ये कार्टून्स आए कि रक्षा बंधन के दिन भाई राखी बंधवाकर उसके बदले में प्याज दे रहा है। पिताजी अपनी बेटी की शादी करते हुए उपहार स्वरूप उसको प्याज देकर घर से विदा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि यह सब आम आदमी का प्रयास है, एक कठिन समय को, एक समस्या को हंसी के साथ जीना।

उपसभाध्यक्ष महोदया, कल लोक सभा में खाद्य सुरक्षा बिल पारित हुआ और मैं नहीं जानता कि इस बिल के पारित होने के बाद गरीब आदमी की थाली में रोटी या चावल पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? परन्तु इस सरकार ने एक काम कर दिया कि उसकी थाली से और उसके भोजन से प्याज को गायब कर दिया। उपसभाध्यक्ष महोदया, प्याज की कीमतों का आसमान पर पहुंचना और रुपये का निरन्तर पाताल की तरफ पहुंचना, दोनों घटनाएं एक ही बीमारी के लक्षण हैं।

आज सदन में प्रश्न काल के समय माननीय वित्त मंत्री जी यह आश्वासन दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। अभी सदन में भी बताया गया है और बाहर भी इस बात की चर्चा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में रुपया अपनी न्यूनतम कीमत 66.08 प्रति डालर के हिसाब से नीचे आ गया । ...**(व्यवधान)**... नरेश जी कुछ बता रहे हैं, मुझे पता नहीं है कि यह होगा या नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर करे यह न हो और यह यहीं पर रुक जाए। क्योंकि अभी डॉलर की कीमत और प्याज की कीमत के बीच प्रतिस्पर्धा है कि डॉलर महंगा होगा या प्याज महंगा होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे एक मित्र ने अर्थव्यस्था के बारे में इस तरह से कहा है कि आज डॉलर escalator पर है, रुपया ventilator पर है, नेशन ICU में है और यह सरकार coma में है। उपसभाध्यक्ष जी, अगर आप चारों तरफ दृष्टि दौड़ाएं, तो आप पाएंगे कि इन चार वाक्यों के अंदर ...**(व्यवधान)**... इस व्यंग्य के अंदर बहुत दर्द छिपा हुआ है और इसमें बहुत सच्चाई है। जो वाणिज्य मंत्रालय अर्थात् कॉमर्स मिनिस्ट्री के statistics हैं, आंकड़े हैं, आप अगर उनको देखें, तो पाएंगे कि जून माह की तुलना में जुलाई में प्याज की कीमत एक महीने में 31 प्रतिशत बढ़ी है। भारत में आलू का प्रयोग हर आदमी के भोजन में होता

[श्री बलबीर पुंज]

है, उसकी कीमत एक महीने में 16 प्रतिशत बढ़ी है और सब्जियों की कीमत में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 16 से लेकर 31 प्रतिशत तक की यह बढ़ोतरी केवल एक माह की है। एक माह में किसी साधारण व्यक्ति की आमदनी 30 से 40 प्रतिशत तक तो बढ़ नहीं सकती। पिछले साल जुलाई, 2012 में जो महंगाई की दर 7.52 प्रतिशत थी, इस वर्ष जुलाई में यह 11.91 प्रतिशत हो गई है। अगर आप देखें कि पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल जुलाई में प्याज की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, वह 145 प्रतिशत हुई है। There is 145 per cent increase in the price of onions in July this year over the price in July 2012. जो सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई माह में 46.59 की बढ़ोतरी हुई है। सच तो यह है कि जब कीमतें इस हिसाब से बढ़ती हैं, तो आम आदमी की क्रयशक्ति purchasing power कम हो जाती है अर्थात् उसकी थाली के अंदर उसी मात्रा में भोजन कम हो जाता है और उसे या तो भूखा रहना पड़ता है या भूखे पेट सोना पड़ता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में double-digit inflation है और अभी नरेश जी बढ़ते हुए ब्याज की दरों की बात कर रहे थे। जो ब्याज की दरों और inflation की दरों में स्वाभाविक रूप से संबंध होता है, क्योंकि अगर inflation की दर ज्यादा होगी, तो आपको ब्याज की दर भी ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो लोगों की जो बचत है, उस पर negative rate of return होगा। इस देश में inflation नहीं है, इसको अर्थशास्त्री भी कहते हैं, यहां पर stagflation है। यह stagflation दो शब्दों की सन्धि से बना है, stagnation and inflation. साधारणत: किसी भी अर्थव्यवस्था में मूल्य कब बढ़ते हैं? जब सप्लाई कम हो और जो मांग है, वह ज्यादा हो अर्थात् जब मांग पूर्ति से ज्यादा बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं, and basically this is an imbalance between demand and supply which means demand exceeds the supply. परंतु उपसभापति जी, यहाँ पर मंजर दूसरा है। This is altogether a different scenario. यहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति है। मांग बढ़ नहीं रही है, demand is not increasing. अर्थात् वह स्टैगनेन्ट है। माँग बढ़ नहीं रही है, वह स्थिर है, वह स्टैगनेन्ट है या गिर रही है।

भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जैसे टी.वी. हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कारें हैं, उनकी मांग में 8 से 10 परसेंट की कमी आई है। इसी तरह से जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, कपड़ा है, उनकी मांग में भी 1 से 2 प्रतिशत की कमी आई है। मांग घट रही है। जब आप मांग में 1 और 2 परसेंट की कमी की बात करते हैं, तो इसका अर्थ इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि अपने देश की जो जनसंख्या है, वह लगभग 2 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है। अगर आपको कंजम्पशन का लेवल वही रखना हो, तो आपकी जो खाने-पीने की चीजों की मांग/डिमांड है, वह at the rate of

2 per cent it must increase so as to keep pace with the rise in population, पर यहाँ तो मांग कम हो रही है. In fact, if you factor in the growth in the rate of population and couple it with fall in demand, you will find actually the demand is falling around by 4-5 per cent. So, you have a very strange phenomenon. Your demand is falling. Your demand for consumer durables is falling. Your demand for necessities of life is falling. But at the same time, inflation is increasing; and as I said earlier there is stagflation.

भारत सरकार आर्थिक विषयों पर जितने भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करती है, डॉक्युमेंट्स प्रस्तुत करती है, मैं उनमें से आर्थिक सर्वे को, इक्नॉमिक सर्वे को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। 2012 और 2013 का जो इक्नॉमिक सर्वे था, उसमें देश की अर्थव्यवस्था का सही विवरण है। मैं उसमें से चार-पाँच पंक्तियाँ क्वोट करता हूं। Madam, here is an excerpt from the introduction to the document, that is, the Economic Survey. I quote here, "...the boost to consumption, coupled with supply side constraints led to higher inflation. Slowdown especially in 2012 has been across the board, with no sector of the economy unaffected. Falling savings without a commensurate fall in aggregate investment have led to a widening Current Account Deficit. Food inflation continues to be higher than overall inflation." This is what the Economic Survey presented by this very Government to this Parliament says. Further it says and I quote: "The danger that fiscal targets would be breached substantially became very real in the current year." Now, that the term of the UPA-II is coming to an end, the growth rate which had touched 8.4 per cent in the last quarter of the NDA rule, has dropped to less than 5 per cent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Please conclude. There are other colleagues from your party who need time.

श्री बलबीर पुंज: और कोई सदस्य बोलने वाले नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): दो नाम और जोड़ दिए गए हैं। Try and conclude.

SHRI BALBIR PUNJ: The industrial growth rate is down to 3.1 per cent and that of manufacturing sector has plunged to 1.9 per cent. The gross fiscal deficit which represents the Government's total expenditure over the revenue generated has grown five folds since the NDA rule and the gap is even widening further and further. Madam, between 1998 and 2003, this varied between Rs.88,900 crores and Rs.1,23,200 crores. In 2011-12, this figure had jumped to Rs.5,21,900 crores.

[श्री बलबीर पुंज]

There was a five fold increase. This depressing scenario is visible in the agriculture sector as well. The foodgrains output has dived to 250.1 million tonnes in 2012-13 from 259.3 million tonnes in 2011-12.

The agriculture growth rate has fallen to 1.8 per cent in 2012-13 from 3.6 per cent. Literally, we are seeing a downfall in all segments of the economy, whether it is industry or agriculture or service sector. The share of agriculture as a percentage of GDP, which stood at 26 per cent...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Mr. Punj, you must conclude because you are taking away the time of your fellow colleagues.

SHRI BALBIR PUNJ: Madam, I will conclude in five minutes.

श्री थावर चन्द गहलोत (मध्य प्रदेश): मैडम, अभी 17 मिनट बाकी हैं।

श्री बलबीर पुंज: मैडम, अभी 17 मिनट बाकी हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): आपके एक और स्पीकर भी हैं।

SHRI BALBIR PUNJ: We have got 30 minutes.

श्री थावर चन्द गहलोत: एक और स्पीकर हैं, वे 10 मिनट बोलेंगे। इनको 5-6 मिनट टाइम और दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): यह आप लोगों का आपसी फैसला है।

श्री थावर चन्द गहलोत: जो इनिशिएट करते हैं, उनको ज्यादा समय मिलना चाहिए।

SHRI BALBIR PUNJ: That is the concern of my Party. Madam, if you interrupt me like this, more and more time will get wasted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): You are losing more time by talking.

SHRI BALBIR PUNJ: It started with you, Madam. I am sorry you are the one who is interrupting me, Madam.

The share of agriculture in the national economy as a percentage of GDP, which stood at 26 per cent and 25 per cent in 1998 and 1999, had declined to 18 per cent in 2008 and further declined to 17 per cent in 2011. This has a very

serious implication. The share of agriculture in GDP is declining very fast, but the number of people who are dependent on agriculture continues to be very, very high, between 60 and 70 per cent. So the number remains the same, the share of agriculture comes down and that means the income distribution becomes skewed against the poor farmers. I would say that the UPA-II particularly, has generated a sort of an economy which believes in jobless growth. Only two million jobs have been created under the UPA-II by now. If you look at the statistics from the International Labour Organization, they reveal that the employment to population ratio which stood at 58 per cent in 2002, declined to 55 per cent in 2009 and declined further to 54 per cent in 2010. Furthermore, between 1998 and 2001 the public sector employed between 19.14 and 19.42 million people each year. In 2009-10, this figure declined to 17.86 million and the trend is pointing downwards.

Madam, nobody else is going to speak from my Party. So I will take all the time. The economy under the UPA II, had inherited a very, very healthy and a robust economy when the NDA left. Now the economy lies in ruins and shambles. The state of the economy under NDA is best summed by the Economic Survey of 2003-04, the last year of the NDA regime. The Survey was presented to Parliament by the UPA-I Government, by Shri Chidambaram, Finance Minister. I quote from the Economic Survey of 2003-04, which says, "The economy appears to be in a resilient mode in terms of growth, inflation and balance of payments -- this is the statement that Shri Chidambaram made -- a combination that offers large scope for consolidation of the growth momentum with continued micro-economic stability. Real Gross Domestic Product is estimated to have grown by 8.1 per cent in 2003-04, buoyed by a strong agriculture recovery of 9.1 per cent from the drought affected previous year".

मैडम, मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि यूपीए-II को एक बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही मजबूत और सशक्त अर्थव्यवस्था विरासत में मिली और वहाँ से पहुँच कर हम इस हालत में क्यों पहुँचे, इसका एक बहुत ही साधारण कारण है और वह कारण यह है कि सत्ता में दो केन्द्र हैं।

प्रधान मंत्री जी के पास पद है, परन्तु उनके पास कोई वास्तविक सत्ता नहीं है और जिनके पास इस सरकार के अन्दर वास्तविक सत्ता है, उनके पास कोई जवाबदारी नहीं है। इसी विडम्बना के कारण आज देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत हुई है।

हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी हैं और उनकी एक कैबिनेट है, परन्तु हम सब यह भी जानते हैं कि यूपीए-II के अन्दर एक दूसरी सरकार चलती है,

[श्री बलबीर पुंज]

जिसको नेशनल एडवाइज़री काउंसिल कहते हैं। वित्त मंत्री का काम है देश के करदाताओं से कर लेकर खजाने को भरना। जो एनएसी है, जिसकी किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, वह इस बात का निर्णय करती है कि कहां पर उस पैसे का खर्च हो। मैडम, इसी विसंगति के कारण देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत है और इसी विसंगति के कारण आज रुपये की कीमत कम हो रही है। आज जितने रुपये में आप एक डॉलर खरीद सकते हैं, शायद उतने रुपये में आप एक किलो प्याज नहीं खरीद सकते।

उपसभाध्यक्ष जी, यह कोई दैवीय संकट नहीं है। This is not some sort of a divine curse. This entire thing is a manmade problem. चाहे वह प्याज की बढ़ती हुई कीमत हो या रुपये की घटती हुई कीमत हो, इस सबके लिए सरकार की अक्षमता और व्याप्त भ्रष्टाचार जिम्मेदार है।

अब हम प्याज का मामला ही लें, चूंकि आज हम प्याज की चर्चा कर रहे हैं। देश में लगभग एक साल में औसतन 160 लाख टन प्याज का उत्पादन होता है। भारत सरकार का आंकड़ा है कि इस वर्ष प्याज का उत्पादन 166 लाख टन हुआ। इसमें से करीब 10% भंडारण या स्टोरेज में खराब हो जाता है और करीब 1.8 मिलियन टन अर्थात् 16 से 18 लाख टन हम लोग निर्यात करते हैं। अगर 166 टन में से आप 35-40 लाख टन निकाल भी दें, उसके बाद भी हमारे पास 125 से 130 लाख टन प्याज बच जाता है, जो इस देश की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी था।

उपसभाध्यक्ष जी, देश में प्याज का संकट नहीं होना चाहिए था, परन्तु उसके बाद भी देश में प्याज का संकट हुआ और आम आदमी को 80 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक प्याज खरीदना पड़ा। इस देश की मार्किट के अन्दर प्याज इतना महंगा बिका, क्यों? इसके पीछे की जो कहानी है, वह बहुत वीभत्स कहानी है और लालच से भरी हुई कहानी है। इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे काला-बाजारिए चलाते हैं, यह उसी का एक रहस्योद्घाटन है। इस साल 21 जून को श्री संजीव चोपड़ा, जो नैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं, उन्होंने प्रदेश सरकारों को पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि नासिक का जो थोक बाजार है, उसमें प्याज की दर 1550 रुपये क्विंटल है। उस समय जून में प्याज की थोक दर 1550 रुपये क्विंटल थी, लेकिन किसान से जो प्याज खरीदा गया था, वह 8 रुपये, 9 रुपये और 10 रुपये किलो की दर पर खरीदा गया था।

उपसभाध्यक्ष जी, आप कल्पना करिए कि किसान से 8 रुपये और 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज खरीदा जाता है और उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते वही प्याज 80 से 100 रुपये किलो हो जाता है। हम सब जानते हैं और यह तथ्य सरकार भी जानती है कि जो प्याज किसान से 8 रुपये और 9 रुपये किलो खरीदा गया और जो थोक बाजार में 15 रुपये

और 15.50 रुपये किलो बिका, उस प्याज को थोक बाजारियों ने स्टॉक कर लिया, भंडारण कर लिया। उस प्याज को उन्होंने बाजार में तब उतारा, जबकि प्याज की दर 45 से 50 रुपये प्रति किलो हो गई थी। अब अगर नासिक के थोक बाजार के अन्दर प्याज के दाम 40 रुपये से 50 रुपये किलो होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से दिल्ली, जम्मू या पंजाब का जो उपभोक्ता है अथवा सुदूर दक्षिण का जो उपभोक्ता है, उसको वह 80 रुपये से 100 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा।

प्याज का कुल व्यापार देश में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का है। इसके अन्दर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्ट राजनेताओं, भ्रष्ट व्यापारियों और कालाबाजारियों की मिलीभगत के कारण देश में प्याज की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज़ या कमी पैदा की गई और उसकी मुनाफाखोरी की गई।

उपसभाध्यक्ष महोदया, देश की आर्थिक स्थिति गम्भीर है। मैं कहना चाहता हूँ कि the people, both common and investors, have lost faith in this Government. This Government is talking in terms of inviting foreign investments to tide over the foreign exchange crisis. A number of so-called reforms have been introduced and the Government is expecting that the depleting foreign exchange reserves will be compensated by the inflow of foreign exchange of investors who will come to areas which have been opened recently. But nothing is going to work. This Government has no credibility. Forget about foreign investors, even domestic investors do not trust this Government. The Indian corporate people are sitting on a cash pile of Rs.9 lakh crores. Even the public sector has a lot of surplus money. But they have no faith in this Government. They are reluctant to risk their money. They are all looking for opportunities abroad. They are going to other countries and setting up plants over there. In this sort of a situation, you can very well expect that production will not increase, the Government will not get taxes and jobs will not be created.

Madam, against this bleak scenario, the things in India will improve only after the people of India throw this Government, lock, stock and barrel, into the dustbin of history, through ballot. And that day is not very far off. Thank you, Madam.

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा कि प्याज और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि के विषय पर आज सदन में जो चर्चा हो रही है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है।

यह चर्चा बहुत समसामयिक विषय पर हो रही है। लेकिन, मुझे थोड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समय देश की जो सबसे ज्वलंत समस्या है, वह है महँगाई और जब यह सत्र समाप्ति की ओर है, तब हम जाते हुए इस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

मैं जो बात कह रहा हूँ, वह चौपाल टाइम्स की बात कह रहा हूँ। चौपाल टाइम्स वह होती है, जो गाँव में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स को क्वोट करेंगे। मैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, जिला परिषद के स्कूल से पढ़ कर आया हूँ, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इकोनॉमिक टाइम्स का कितना ही हवाला दें, इस देश की चौपाल टाइम्स, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर चर्चा करती है, उसने आपको महँगाई के मामले पर सौ परसेंट फेल कर रखा है, 99 प्रतिशत भी नहीं, पूरे सौ परसेंट। इसलिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मंत्री जी का जवाब आएगा तो बड़े लोक लुभावने भाषण होंगे, आंकड़े होंगे, मुद्रास्फीति होगी, जी.डी.पी. होगी, विकास दर होगी, पिछली सरकारों से तुलना होगी, पिछले वर्ष से तुलना होगी और पिछले फाइनांशियल ईयर से तुलना होगी।

"मुझे पतझड़ों की कहानियाँ सुना-सुना के न उदास कर,
नये मौसमों का पता बता, जो गुजर गया, सो गुजर गया। "

सवाल इस बात का होना चाहिए कि अब हम इसको काबू कैसे करें? बहुत विद्वान साथियों ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन जिम्मेदार आदमी के द्वारा कभी इस सदन में यह नहीं कहा गया कि हम यह करेंगे, हम ऐसा करके मानेंगे, हम ऐसा कर देंगे। मैं बहुत अदब के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी से माफी मांगते हुए यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने देश को आश्वस्त किया था। हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन प्रधान मंत्री जी हमारे देश के होते हैं, वे पूरे देश के प्रधान मंत्री हैं और जब प्रधान मंत्री जी बोलते हैं, तो देश बहुत गंभीरता से सुनता है। पहले तो वे बोलते बहुत कम हैं, लेकिन जब कम बोलने वाला व्यक्ति बोलता है, तो उसकी बात में और भी अधिक गंभीरता होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अन्य संसद सदस्य भी मेरी बात से संबद्ध होंगे कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने दावा किया था कि 100 दिन में हम महंगाई पर काबू पा लेंगे। यह मैं सदन के माध्यम से, मोहतरमा, आपके माध्यम से अपने देश के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी को केवल याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि जहां तक मेरी गिनती ठीक है, मेरा गणित ठीक है, 100 दिन से बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं और मुझे लगता है कि कहीं सरकार ने समय से पहले निर्णय ले लिया, तो 100 दिन तो अब चुनाव के बचे हैं। अब 100 दिन चुनाव के बचे हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है। इसलिए हमारे माध्यम से, सदन के माध्यम से, मोहतरमा, आपके माध्यम से देश की जनता जानना चाहती है कि ये 100 दिन कब पूरे होंगे? क्या ये पूरे हो गए हैं? अगर पूरे हो गए हैं, तो क्या महंगाई कम हुई है? अगर ये पूरे नहीं हुए हैं, तो आप कब तक महंगाई को कम करेंगे?

अभी का विषय है -- प्याज और अन्य आवश्यक वस्तुएं। जहां तक अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं, उनमें सबकी अलग-अलग प्राथमिकता है। इस देश के धनाढ्य लोगों के लिए अन्य

5.00 P.M.

आवश्यक वस्तुओं में एयर कंडीशन्ड हो सकते हैं, एसयूवी गाड़ी हो सकती है, हवाई जहाज की यात्रा हो सकती है, ब्रांडेड कपड़े हो सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों की प्याज एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं में जो चीजें हैं, उनकी सूची मैं बता दूं - आटा, चावल, तेल, घी, नमक, मसाले, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च, साबुन, दाल, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, पढ़ाई। जैसे प्रोटीन्स दाल से मिलती हैं, हम अभी प्याज के बारे में कह रहे हैं, लेकिन दाल के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। आपने तो स्वाभिमानी आदमी का स्वाभिमान ही छीन लिया। आप खुद्दारी छीन रहे हैं। एक ईमानदार आदमी बड़े गर्व के साथ कहता था कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, प्याज के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन आज वह प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता है। आम आदमी हम लोगों से कहता था कि कभी भी चले आइए, दाल-रोटी में कोई कमी नहीं है। अब जाने से पहले सोचना पड़ता है क्योंकि दाल-रोटी में कमी आ गई है। दाल हो सकती है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है और दाल की मात्रा कम हो गई है।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर कुदरती तौर पर या प्राकृतिक कारणों से महंगाई हो तो माफ किया जा सकता है। नासिक में बारिश कम हुई, प्याज की जोत कम हुई। दिल्ली में सब्जियां हरियाणा, पंजाब से आती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, नदियों में बाढ़ आ गई है, सड़कें टूट गई हैं, तो थोड़ी देरी हो सकती है, इसके लिए आपको माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर जमाखोरी हो रही है, मुनाफाखोरी हो रही है और कृत्रिम अभाव दिखाया जा रहा है, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। दूरदर्शन ने बताया है कि कहीं एक-आध जगह छापे पड़े हैं, वहां पर प्याज गोदाम में पड़े हुए थे, यह किसकी जिम्मेदारी होती है? मैं फिर अदब के साथ माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, प्रधान मंत्री जी इस देश में इकनॉमिक रिफॉर्म्स और अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी टीम भी बहुत अच्छी चुनी। चिदम्बरम जी गृह मंत्रालय देख रहे थे, वे वहां से वित्त मंत्रालय में आए, वे अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को हम विपक्ष के लोगों ने नहीं बनाया है।

यह आपकी पसंद है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, लेकिन गरीबों का मजाक उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि पाँच रुपये में कहीं भोजन मिलता है, कहीं 15 रुपये में मिलता है और एक साहब ने तो इसे दो रुपये में मिलने की बात कह दी। दो रुपये में तो भूसा भी नहीं मिलता है। पाँच रुपये में तो आप भूसे से भी पेट नहीं भर सकते। लेकिन जो 15 रुपये में भोजन कराने की बात कह रहे हैं, उसमें प्रोटीन कितना है, उसमें विटामिंस कितने हैं, उसमें मिनरल्स कितने हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं? डाइटिशियन, जो कि डाइट प्रेस्क्राइब करता है, क्या उसके अनुसार 1800 कैलोरी 15 रुपये में मिल सकती है? यह कौन-सी परिभाषा है कि गाँव में अगर किसी की इनकम 27 रुपये है, तो वह गरीब नहीं है और 33 रुपये में वह अमीर

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

नहीं है? मैं नाम लिए बिना योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि मैं पंच-सितारा संस्कृति का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन शायद वे कभी वहाँ खाना खाने गए होंगे। वहाँ आप केवल एक दाल, एक सब्जी, रोटी, चावल और सलाद का आर्डर करेंगे, तो इसका बिल 10 हजार रुपये से कम नहीं आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि हम 10 हजार रुपये कम बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर चार लोग खाना खाने मौर्या शेरेटन वगैरह में जाएँ, तो इसका 10 हजार रुपये का बिल आ जाता है। चौधरी साहब, वहाँ टिप देने का क्या रिवाज है? यह क्लेम नहीं है, लेकिन संभवत: यह कहा जाता है कि यह 10 पर्सेंट दी जाती है। जो लोग अगर 10 हजार का भोजन करते हैं, तो वे एक हजार तो टिप में दे देते हैं। जो लोग एक हजार रुपये की टिप देते हैं, वे हमें 27 रुपये में रहने का शऊर सिखा रहे हैं! आप गरीबों को मत हटाइए, गरीबी हटाइए और जब तक आप गरीबी नहीं हटा रहे हैं, आपको किसी को जलील करने का अधिकार नहीं है और न ही इस प्रकार की परिभाषाएँ देने का किसी को अधिकार है। आज इससे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग, गाँव के लोग और बैकवर्ड क्लास के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इससे माइनॉरिटीज़ के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जिन्हें सच्चर कमीशन ने कहा है कि आपकी स्थिति दलितों से भी खराब है। 1800 कैलोरी का भोजन! लोग तो यह तक कहते हैं कि मौसम का हर फल खाना चाहिए। अगर आप काजू-किशमिश लाकर दें, तो बच्चे यह बता नहीं पाएँगे कि यह काजू है, किशमिश है, चिलगोजा है या बादाम है। इस देश के बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ...**(समय की घंटी)**...

मैं यह कहना चाहूँगा कि गरीबों की जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, उनकी कीमतों को आप कम कीजिए। इसके साथ ही, मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कृत्रिम अभाव को समाप्त करना चाहिए। हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं और उसके लिए डॉलर्स में जो भुगतान करते हैं तथा हम कोयले का इम्पोर्ट करते हैं और उसके लिए डॉलर्स में जो भुगतान करते हैं, मेरी समझ से यही महँगाई का कारण है। यह देश खनिज-सम्पदा से भरा पड़ा है और इसके भूगर्भ में पता नहीं क्या-क्या है। आज खनिज सम्पदा से धनी राज्यों के लोग गरीब हैं। हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में दुनिया भर की खनिज-सम्पदा उपलब्ध है। आप नैचुरल गैस के बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं। आप ओएनजीसी को खुला नहीं छोड़ रहे हैं। आप किसके दबाव में उनको रिसर्च नहीं करने दे रहे हैं? हमने केवल एक "बॉम्बे हाई" की खोज की है। क्या हमारी अन्य जगहों पर नैचुरल गैस नहीं है? यह है, इसे कौन पता करेगा? इसे गाँव-देहात के किसान तो पता करेंगे नहीं। इसे जिनको पता करना है, वे अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए घाटे की खेती हो रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक्यू, बघेल जी।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: मुझे यह विरोधाभास आज तक समझ में नहीं आया कि नासिक का किसान कहता है कि हम तो मर गए, प्याज के कारण हम घाटे में चले गए।

हमारे आगरा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद आदि जिलों के आलू किसान रो रहे हैं, वे कहते हैं कि आलू बहुत महँगा है और हमें भी पिक्चर हॉल में "अंकल चिप्स" खरीदते समय सौ बार यह सोचना पड़ता है कि हम इसे खरीदें या न खरीदें? महाराष्ट्र में कपास का किसान परेशान है और यहाँ जाड़े के मौसम में एक रजाई में पाँच-पाँच लोग और बच्चे सो रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक्यू। बघेल जी, प्लीज़ आप अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: इस प्रकार, कपास पैदा करने वाला किसान भी रो रहा है और रजाई खरीदते हुए उपभोक्ता भी रो रहा है। नागपुर का संतरे का किसान परेशान है और हम यहाँ संतरे को खरीदते हुए परेशान हैं। कश्मीर का सेब-उत्पादक किसान परेशान है और हम सेब को खरीदने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। मोहतरमा, बाजार-व्यवस्था को कुछ ऐसा किया जाए कि यह स्थिति पैदा न हो। मैं महँगाई रोकने के कुछ तरीके सुझाना चाहूँगा। चाहे दिल्ली की आजादपुर मंडी हो, हमारे आगरा की मंडी हो या मेरठ और मुजफ्फरनगर की मंडी हो। वहाँ किसान के पास से पाँच बजे सुबह जो सब्जी आती है, उसका उस समय का भाव और जब वह चार घंटे, तीन घंटे, दो घंटे और एक घंटे बाद छोटी-सी ठेली के माध्यम से कॉलोनी में पहुँचती है, तो उस समय के उसके भाव में चार गुना का अंतर होता है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): थैंक्यू, बघेल जी। श्री शान्ताराम नायक जी।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: मोहतरमा, क्या किसी भी आदमी को ऐसा करने का अधिकार दिया जा सकता है?

आपने किसान से सब्जी सुबह 5 बजे खरीदी और उपभोक्ता को चार गुनी कीमत पर दी। इस प्रकार सबसे घाटे में रहती है आखिर में खरीदने वाली गृहिणी और घाटे में रहते हैं किसान पैदा करने वाले।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): बघेल जी, आपका समय हो गया है, प्लीज, आप दूसरों का मौका मत लीजिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: जहां तक सोने की बात है, देहात से सोना गायब है। अब गांवों में औरतों के शरीर पर सोना नहीं है। अमीरी सोने-चांदी की दुकानों में इठलाती है, गरीबी कान छिदाती है और तिनका डाल लेती है।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी): शान्ताराम नायक जी, आप बोलिएगा।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: हमारे गांव, देहात की महिलाएं कृत्रिम आभूषण पहन रही हैं। मुझे लगता है कि अब मेरा समय हो गया है, लेकिन बहुत बोलना चाह रहा था। यह मैं थोड़ा सा आश्वासन चाहूंगा, चाहे आप ज्यादा समय न दें। लेकिन कोई जिम्मेदार आदमी यह जरूर आश्वस्त करे कि यह सौ दिन पूरे कब होंगे? यह जो सौ दिन हैं, ये सौ दिन सास वाले हैं या खूसट सास के सौ दिन हैं?...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... कोई फायदा नहीं है।...(व्यवधान) नायक जी, आप बोलिए।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल: *

SHRI SHANTARAM NAIK (Goa): Madam, from our side, I share the sentiments of the House and the concerns as regards price-rise. We would not like to conceal anything. In fact, I would like to summarise the present situation in the form of one lyric, which I heard many years ago. पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे लेकर जाते हैं मुट्ठी में शक्कर आती है। This is the reality, and we would not like to run away from this reality. But, in our country, as it is, vagaries of monsoon have to be kept in mind. कब कहीं drought आता है, कहीं flood आता है, cloudbursting होती है, यह हमारी geographical reality है। इस रियेलिटी के अंदर क्रॉप का जो सिस्टम चल रहा है वह अफेक्ट होता है। यह रियेलिटी सब को ध्यान में रखना जरूरी है।

Secondly, on this basis, there is a system of demand and supply. मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई का गैप होता है, तो प्राइस राइज होता है। जो डिमांड पब्लिक की है, आम डिमांड, मिनिमम डिमांड उतनी डिमांड के साथ सप्लाई मार्केट में नहीं आई तो प्राइस राइज होता है। यह भी रियेलिटी है। भिन्डी का भाव दस रुपए ज्यादा हो गया तो Prime Minister responsible है। यह जो साइक्लॉजी है और यह जो तरीका है कुछ लोगों का, वह सही नहीं है। भिन्डी का भाव दस रुपए क्यों बढ़ा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। यहां तक यह exaggeration नहीं है। यही तो आप कहते हैं बार-बार इन्ही शब्दों से, यह हमारा कन्सर्न है। सड़क का आम आदमी जो दुखी है, अगर वह कहने लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्याज, भिन्डी, चावल, शक्कर जरूरी हैं। उनको पता नहीं है कि कौन लाता है, कहां से लाता है। लेकिन आप जैसे literate person, जब भिन्डी का भाव बढ़ता है तो पी.एम. को दोषी ठहराते हैं, उसका हमें दुख होता है। This is a matter of concern. Recession अमेरिका में आया, दो-दो, तीन-तीन साल तक बड़ा recession रहा। लोग घर छोड़कर चले गए, भाड़ा पे नहीं कर सके, आउट पोस्ट में रहने

*Not recorded.

लग गए, छोटी सी कार में रहने लगे, हालत बुरी हो गई, वहां से छोड़कर लोग अपने गांव आ गए, अपने देश में आ गए। फिर भी ओबामा जीत गए। किसी ने ओबामा को दोषी नहीं ठहराया।

वहां देश की ऐसी हालत हुई, लेकिन वहां के लोग इकॉनोमिक सिस्टम को समझते थे क्योंकि वहां इतनी लिटरसी है। दुर्दैव से हमारे देश में उतनी लिट्रेसी नहीं है। इसलिए हम लोगों को उतना समझा नहीं पाते। उसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन यह सच्चाई है कि अमेरिका में जो हालत हुई, उसके बावजूद ओबामा चुनाव जीत गए। Current economic position is nothing close to 1991. The lowest growth rate under UPA was the highest under NDA from 1998 to 2004. आप इस के फिगर्स निकाल कर देख लीजिए। आप अभी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके जमाने में आप क्या कर रहे थे, आप कैसे सरकार चला रहे थे, लोगों की हालत कैसी थी, इस बारे में आप खुद सोचें? महाराष्ट्र में सब जगह बड़ा सूखा पड़ा तो ओनियन का प्रोडक्शन भी 10 परसेंट घटा। आप जानते हैं, 10 परसेंट की सप्लाई बहुत बड़ी होती है। महाराष्ट्र जोकि ओनियन की बेसिक मंडी है, उसमें 10 परसेंट घटा है, लेकिन उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। राजस्थान में बम्पर क्रॉप हुई, जिसे वे उस वक्त बेच नहीं पाए। दूसरे साल उन्होंने ओनियन की पैदावार कम की, जिस की वजह से 30 परसेंट प्रोडक्शन गिर गया। यह भी सच्चाई है, supply gets affected on account of heavy rains in the field. It also gets affected because transportation gets affected. डीजल की प्राइस इंक्रीज होती है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन वह भी अपने हाथ में नहीं है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, कोई कह सकता है कि वह सरकार के हाथ में है? वह आप लोगों को बताने के लिए कहते हैं, लेकिन डीजल या पेट्रोल जैसे जो प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट करते हैं, उनके भाव सब्सिडाइज करने के बावजूद भी बढ़ते हैं और फिर आम चीजों की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। इसके लिए सस्ते दर पर बेचने के स्टॉल्स लगाने जरूरी हैं ताकि लोगों को सब्जी व रोज इस्तेमाल की चीजें मिल सकें। I am not an economist but I feel that the prices will certainly fall when the kharif crop products start coming to the market. It is presumed that somewhere at the end of August or in the beginning of September when onion starts coming from Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, etc., these prices are bound to fall and fall heavily also. किसानों को नुकसान तब भी होता है जब कि ज्यादा प्राइसेस गिरते हैं। इसलिए जब सामान मंडी में आएगा तब भी प्राइसेस नीचे आएंगे। अपना देश एनुअली 10 से 15 टके प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करता है। हमने इस साल ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल से इस साल थोड़ा कम ही किया है। आज इस पर भी बहस हो रही है कि एक्सपोर्ट बैन किया जाए या नहीं। हमारा ओनियन लंका, बंगदेश, रशिया, मॉरीशस, चाइना, सिंगापुर और गल्फ कंट्रीज में जाता है। On an average, 10 per cent, as I said, is being exported. हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, पवार साहब का मत, जैसा अभी तक अखबार में आया है, एक्सपोर्ट के खिलाफ है। उसके भी कुछ कारण हैं। उनका कहना है कि अगर हम अचानक

[Shri Shantaram Naik]

एक्सपोर्ट बैन करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्रेडेबिलिटी नीचे चली जाएगी। So there was a point here. अनफॉर्चुनेटली हमारे आम आदमी की समझने की ताकत इतनी नहीं है, यह भी सच्चाई है।

Therefore, this has to be considered. Now, in Delhi market, the role of retailers also has to be seen. बलबीर पुंज जी अभी यहां नहीं हैं, उनको दिल्ली मार्केट की थोड़ी जानकारी है। ट्रेडर्स, जो उनके दोस्त भी हैं और दिल्ली वाले मेम्बरों के बड़े दोस्त हैं, वे पांच-दस परसेंट कैसे बढ़ाते हैं? दिल्ली वाले ट्रेडर्स के भाव कैसे बढ़ते हैं, स्टॉक होते हुए भी कैसे बढ़ते हैं, यह सब इनको मालूम है। ये उनके सपोर्टर्स हैं। ये आम आदमी के सपोर्टर्स नहीं हैं, तो अगर वे ...(**व्यवधान**)...

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu): Madam, the hon. Member is saying that the BJP leaders and the traders are increasing the prices. The BJP is also not saying anything. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Why are you bothering? ...*(Interruptions)*... He has not yielded. ...*(Interruptions)*... Have you yielded, Mr. Naik.

SHRI SHANTARAM NAIK: No, Madam. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): If traders are increasing the prices, is the Government....*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): It is not the conversation that we can have. Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Is the Government ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM NAIK: I am giving you another example. I am giving you an example and also enlightening your knowledge how the BJP Government in Goa has imposed 'entry tax' on vehicles coming from other States. ...*(Interruptions)*... This led to increase in prices of tomatoes, potatoes, and other vegetables. The prices of every item has increased in Goa because of the BJP Government. ...*(Interruptions)*... When the mining people were suffering there, the BJP Government, at that time, ...*(Interruptions)*... You are in-charge, Madam. ...*(Interruptions)*... You know it. You have gone there. ...*(Interruptions)*... You know what your Chief Minister has done there. ...*(Interruptions)*... He has imposed 'entry tax'. ...*(Interruptions)*... Did people not come to you to complain against your own

Government? Please tell me. ...*(Interruptions)*... Did your own workers not come to complain? ...*(Interruptions)*... Everybody is suffering. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Please; please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM NAIK: Everybody is suffering because of the 'entry tax', which has illegally and arbitrarily been imposed by your Government. ...*(Interruptions)*...

I would certainly like to mention here that Media has also to play an effective role. They have to enlighten people. There is no doubt about it. Media people may find fault with me. But the way the news items regarding rising prices or inflation are brought in Media that itself gives rise by 10 per cent. Even a statement of the Finance Minister on the Budget may sometimes increase prices, or, even the Stock Market can ...*(Interruptions)*... In the same way, whatever is expressed in the Media regarding inflation that makes an impact. If there is a bumper crop because of the efforts of farmers or agriculturists or because of the efforts of an individual Minister or an MLA, does the Media report that it is because of the efforts of farmers or agriculturists, or whoever it is? No. ...*(Interruptions)*... Or, if some good variety of paddy seeds or other seeds has been introduced, does the Media appreciate and project that in their reports? They don't do it. Therefore, I say that Media has also to play an effective role. I don't blame Media, but it has to play an effective role to enlighten people about the economic situation in its own simple way so that they can understand it. This will help the nation. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Shri Sitaram Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Madam, if you don't mind, I would like to speak tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Shri Kunal Kumar Ghosh. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O' BRIEN (West Bengal): Madam, just a minute. If everyone decides that he will speak day-after-tomorrow, we will also speak day-after-tomorrow. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): That's up to you. If you choose not to speak today, that's up to you. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O' BRIEN: If we can finish the discussion today, we can get the reply from the hon. Minister. ...*(Interruptions)*... Madam, are we finishing the discussion and getting a reply from the Minister today or are we carrying this over?

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): We have the Minister sitting with us. If someone wants to forsake his speech ...

SHRI DEREK O'BRIEN: No, no. I am just asking. The sense is that we finish the discussion and get a reply from the Minister today and wrap up the debate.

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Let us first finish the discussion in the allotted time. If we can conclude it, then, obviously, other things will conclude.

SHRI DEREK O'BRIEN: Then, we will also speak the day after tomorrow.

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): That's up to you.

SHRI DEREK O'BRIEN: So, we will also speak the day after tomorrow. ...*(Interruptions)*... What is the understanding, Madam?

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): The understanding is that you have a given time allotted to you. Then, there is a given time allotted to conclude this discussion. As per the procedure, you will have ... ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: That's fine. ...*(Interruptions)*... But the discussion should be finished today. Are we here or some of our prima donnas are here?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): What is the decision? ...*(Interruptions)*... Are we concluding the discussion today, or, are we continuing the discussion the day after tomorrow?

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.)

AN HON. MEMBER: Let us conclude today, Sir. ...*(Interruptions)*...

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh): Sir, how many speakers are there?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me see.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, there are twenty speakers. We have already counted it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are, at least, eighteen speakers.

DR. NAJMA A. HEPTULLA: Sir, two-and-a-half-hour discussion should be finished, at least, in three hours. But we cannot give the whole day just for one discussion. We started it, and let us finish it. Tomorrow is Janmashtami. Everybody wants to go early. So, let us finish it at 5.30 p.m. ...*(Interruptions)*... Sir, at the fag end of the day, we are discussing the price rise. The day after tomorrow, we can take it afresh. So, we might have some more figures to add. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your suggestion? ...*(Interruptions)*...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, we should discuss it on Thursday morning.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, today, we can discuss it only up to 5.30 p.m. What is Yechuriji saying?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, it is already 5.25 p.m. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश): सर, हो सकता है कि कल प्राइस डाउन हो जाए और यह डिस्कशन किसी काम का न रहे।...(**व्यवधान**)...

جناب محمد علی خان : سر، ہو سکتا ہے کہ کل پرائس ڈاؤن ہو جائے اور یہ ڈسکشن کسی کام کی نہ رہے ...(مداخلت)...†

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ali, perhaps, you don't know the importance of Janmashtami. They are asking for adjourning it early for Janmashtami.

---

†Transliteration in Urdu Script.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the request has come saying that tomorrow, because of Janmashtami, many of the Members want to go back to their constituencies, and they have to leave for their flights which are scheduled at about 6.00 p.m. or so. They requested that. I don't want to name them. But all of them have requested that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. If that is the sense, we will sit up to 5.30 p.m. and then the discussion will be...

श्री थावर चन्द गहलोत: सर, साढ़े पांच तो हो गए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, there are five minutes more. I will call Mr. Kunal Kumar Ghosh. वे आज नहीं बोलना चाह रहे। Then, Mr. Tyagi; he is not here. Then, Shri Rathinavel.

SOME HON. MEMBERS: Sir, it is his maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Then, I will call Dr. Ramalingam.

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब): सर, आप हमें बोलने का समय दे दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Dr. Ramalingam. I have called him. So, we will then stop it at 5.30 p.m..

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

My great Dravidian Party founder leader, *Thanthai Periyar,* used to say *'vengayam'*, i.e., onion. Whenever he spoke from the dais, he used the word *'vengayam.'* It means, you keep peeling it, and in the end, there is nothing. But the onion is a big issue now. Today, we are discussing it and the day after tomorrow, we are again going to discuss it. The entire country is suffering due to abnormal increase in the prices of essential commodities, particularly, onion. In 2007, its price was Rs. 5 per kg; in 2010, its price was Rs. 20 per kg. Now, it is selling at Rs. 60 per kg. Sir, not only the price of onion is high, but there is a heavy price rise in every essential commodity also.

But all this rise is only in the market price, not in the farm price. The farmers are selling their produce just for Rs. 10 per kg; the onion producers are selling it at only Rs.10 per kg. So, the economic condition of our country is in a shambles.

Sir, I would like to invite the attention of the House towards the fact that all economic indicators present a very gloomy picture. The value of rupee has been continuously depreciating. In April 2013, it was Rs.54.83 per US dollar. On the date of commencement of this Monsoon Session, it was Rs.60.82 per US dollar. Two days earlier, it was Rs.65 per US dollar and today, it is Rs.66 per US dollar. The rate of inflation has also become a matter of concern. Inflation rates stood at 4.86 per cent in June, 2013. It was recorded as 5.79 per cent in July, 2013.

Sir, the growth in the index of industrial production was one per cent during April-May, 2013-14; for 2012-13, this was 0.6 per cent. In this sphere also, we are facing crucial fall in industrial production. The rate of Gross Domestic Product, GDP, is also seeing a crisis.

Sir, all the indicators that I have mentioned above loudly state that all is not well. If this trend continues, this Government will not be able to achieve inclusive growth, which was the main agenda for our UPA in its election manifesto. ...*(Interruptions)*... Previously, at the time of the election manifesto, it was our UPA. I said 'our' UPA. If you don't like it, I won't say it.

Sir, hoarding of essential commodities is one of the reasons for escalation in the prices of essential commodities. Also, we should not overlook the increase in production cost of agro-products as far as the farmer is concerned. The Government should come forward to take strict action against the hoarders and ensure that there is free supply of essential commodities in the market. My beloved leader, when he was the Chief Minister, had introduced in 1996, hundred *Uzhavar Sandai*, that is, farmers' markets, where farmers could sell their products directly in the market. It was very successful. This model could be introduced all over the country. Only then can we control prices.

Please, Sir; you have agreed to some Members when they said we would have further discussions day after tomorrow, but you can't allow two or three minutes to me!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I didn't ask you to stop.

DR. K.P. RAMALINGAM: But, Sir, you were looking at me and looking at the time!

[Dr. K.P. Ramalingam]

Sir, when it is possible for the Government, particularly this Government and our Finance Minister, to introduce Audi cars, Samsung Galaxy Tabs, i-Phones, etc., on the Indian streets, can't it be possible for the Government to curb the menace of hoardings? Yes, it is possible, but the Government should be clean and honest. Then it would be possible; otherwise, it is not possible. Be sensitive to the people's needs. Be sympathetic towards the aspirations of the people. Get into the reality. Whenever the prices of agricultural commodities rise, we all cry. Members from this side, the other side, CPI, all cry, but we never bother about the rise in prices of industrial products, such as pen, paper, soap, etc. To tackle price-rise, I would make some suggestions to the Government. Whenever there is a hike in the prices of onion, they immediately go in for import. The total period of cultivation of onion crop is just 82 to 90 days. But now, after the price-hike, 32 days have already gone. The Indian farmers have been cultivating onions on a large scale. At present, they are cultivating only 30 per cent of the fields, and now, if you go in for imports, after the harvest, the farmer will be doomed.

We have to control all those things. Don't think of importing agricultural products in India. We have to encourage the producers. If we encourage the farmers, you will definitely see the farmers producing farm food. If you write sugar on your paper, it won't help. You have to produce sugar and give it to people, that will be a help. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the discussion will continue on the next day. I am now taking Special Mentions. I would request hon. Members to lay them on the Table.

SPECIAL MENTIONS ... *(contd.)*

Demand to take urgent measures to prevent incidents of rape with mentally retarded women and to also rehabilitate them

SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA (Gujarat): Sir, there are many cases coming to light that mentally retarded women are targeted for rape by anti-social elements. Due to lack of awareness, they do not identify the criminals and such criminals escape from legal net. In many cases, when such women become pregnant and